भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1314

03 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: सोयाबीन की मूल्य लागत

1314 डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे कुछ प्रमुख हितधारक राज्यों में सोयाबीन की लागत में लगातार कमी को रोकने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त कारक ने देश के खाद्य तेल आयात नीति को प्रभावित किया है और सोयाबीन की कीमत पर प्रभाव डाला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): सोयाबीन की कीमत खाद्य तेल बास्केट और ऑयल मील की अंतरराष्ट्रीय कीमतों सहित अन्य कारकों के अतिरिक्त बाजार की मांग और आपूर्ति क्षमताओं पर निर्भर करती है।

सरकार, प्रत्येक वर्ष कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर सोयाबीन सहित 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करती है। सरकार, फसल की चरम कटाई अवधि के दौरान जब कभी भी बाजार कीमतें अधिसूचित एमएसपी से कम हो जाती है तब मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत सोयाबीन की खरीद करती है, बशर्ते कि वह उपज निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के अनुरूप हो। सरकार ने वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के दौरान, सोयाबीन की प्रभावी खरीद और किसानों तक एमएसपी का लाभ पहुंचाने के लिए गुणवत्ता पैरामीटर में एक-बारगी छूट भी प्रदान की है।

घरेलू उत्पादन और मांग/खपत में अंतर को पाटने के लिए देश में खाद्य तेलों का आयात किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार के आयात से किसानों और अन्य हितधारकों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, सरकार खाद्य तेल आयात नीति में परिवर्तन करती है। 14 सितंबर, 2024 से कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चे पाम तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है, जिससे कच्चे तेलों पर प्रभावी शुल्क 27.5% हो गया है। इसके अतिरिक्त, रिफाइंड पाम तेल, रिफाइंड सूरजमुखी तेल और रिफाइंड सोयाबीन तेल पर मूल सीमा शुल्क को 12.5% से बढ़ाकर 32.5% कर दिया गया है, जिससे रिफाइंड तेलों पर प्रभावी शुल्क 35.75% हो गया है।

*****